भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †3206
दिनांक 11.03.2026 को उत्तर देने के लिए

खानों का निजीकरण

†3206. श्री शफी परम्बिलः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार खनन क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदा कंपनियों में विनिवेश करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) खनन में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के वर्तमान लाभ का ब्यौरा क्या है; और
(ग) खनन में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) की दक्षता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दूबे)

(क): मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रम (पीएसयू), अर्थात्

(i) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको); (ii) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल); और (iii) मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल) हैं। वर्तमान में, इन पीएसयू में विनिवेश करने की मंत्रालय की कोई योजना नहीं है।

(ख): पिछले तीन वित्त वर्षों में, इन पीएसयू द्वारा अर्जित कर पश्चात् लाभ का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वित्त वर्ष	कर पश्चात् लाभ (करोड़ रुपये में)		
		नालको	एचसीएल	एमईसीएल
1	2022-23	1,544	295	14

2	2023-24	2,060	295	70
3	2024-25	5,325	468	84

(ग): खनिज उत्पादन और रोज़गार सृजन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने विभिन्न परिवर्तनकारी उपाय किए हैं। पीएसयू की दक्षता बढ़ाने के लिए किए गए कुछ प्रमुख उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) बेहतर अयस्क पुनः प्राप्ति के लिए रिमोट ऑपरेशन और पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी सहित आधुनिक प्रौद्योगिकी, उन्नत मशीनरी, डिजिटल सिस्टम और उत्पादन प्रक्रियाएं अपनाना।

(ii) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी): प्रौद्योगिकी, प्रबंधन कार्यपद्धतियों और निवेश के लिए निजी फर्मों के साथ सहयोग।

(iii) खान डेवलपर और ऑपरेटर (एमडीओ) की नियुक्ति और गैर-प्रमुख कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग।

(iv) डेटा-संचालित निर्णय लेना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और 5जी नेटवर्क सहित मजबूत संचार प्रणाली।

(v) दक्षता की निगरानी के लिए प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतकों (केपीआई) की नियमित समीक्षा।

(vi) सतत खनन पर जोर देने के साथ आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए खानों की स्टार रेटिंग का कार्यान्वयन।

*****